ont>

12.24 hrs.

Title: Regarding levying of excise duty on powerloom industry and imposition of Value Added Tax (VAT).

अध्यक्ष महोदय : मैं राम जी लाल सुमन को बोलने का मौका दे रहा हूं। उन्होंने Strike by traders against Value Added Tax (VAT) के संबंध में नोटिस दिया है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मूल्य वर्धन बिक्री कर जिसे वैट कहा जाता है, उस सवाल पर पूरे देश के व्यापारियों ने आंदोलन किया है। 7 तारीख को जो रेडीमेड गारमैंट्स पर उत्पादन शुल्क लगाया गया, उस सिलसिले में दिल्ली में लोगों ने प्रदर्शन किया। कल 8 तारीख को पूरे हिन्दुस्तान के व्यापारियों ने वैट के खिलाफ उस समय प्रदर्शन किया, उस समय दिल्ली में अपनी शक्ति का इजहार किया जब भारत सरकार प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ वैट के सवाल पर चर्चा कर रही थी।

यह बहुत गंभीर सवाल है और वैट से जो छोटे व्यापारी हैं, उपभोक्ता हैं, वे दोनों ही बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जितनी जगह माल बिकेगा, उन सब जगह पर टैक्स लगेगा। इससे ज्यादा गंभीर सवाल और कोई नहीं हो सकता। इसके लागू हो जाने से एक तरह से इंस्पेक्टर राज कायम करने की व्यवस्था हमारे देश में हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो परेशान आदमी है, उसे न्याय लेने का हक नहीं होगा। सरकार किसी अधिकारी की अध्यक्षता में कोई कमेटी बना देगी और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, वे ही लोग उसकी सुनवाई करेंगे। अब तक सौ चीजें ऐसी थी जो कर मुक्त थीं। अब इसके चलते खाली 36 चीजें ऐसी हैं जो वैट कर से मुक्त हैं। चीनी, कपड़ा, बीड़ी, सिगरेट, गुड़, पानी, नमक, रोटी इत्यादि इन सब चीजों पर भी वैट लगेगा। इससे ज्यादा गंभीर सवाल कोई दूसरा नहीं हो सकता। सरकार ने कहा है कि हमने दो महीने क लिए इसे स्थगित कर दिया है और एक जून से फिर लगाएंगे। यह पूरी तरह वापस होना चाहिए। यह बहुत गंभीर सवाल है और फिर सरकार कहती है कि 16 राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है। दिल्ली, यू.पी. और राजस्थान की सरकारों ने कहा है कि हमेंâ€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन सब वियों पर दो मिनट में बोलना चाहिए। ज़ीरो ऑवर में भाग नहीं होना चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन : केवल आधा मिनट लूंगा। केरल की सरकार ने विधान सभा में वैट लागू करने का प्रस्ताव अपनी तरफ से पास किया और फिर केरल की सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। यह गंभीर सवाल है। ये जो बीजेपी के लोग बैठे हैं, इनका आचरण दोहरा है। कल मदनलाल खुराना वहां भाग करने गये थे लेकिन वापस कर दिये गये कि चले जाइए। इनका आचरण भी दोहरा है। जहां तक रेडीमेड गारमेंट्स का सवाल है,â€¦ (व्यवधान)31 मार्च से यह काम पूरी तरह से बंद है, मुझे मालूम है। इस संबंध में कई संगठनों के लोग आपसे भी मिले थे। रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन शुल्क बढ़ा है, वह वापस होना चाहिए और वैट टैक्स सरकार अविलम्ब वापस ले।â€¦ (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। सीधी-सीधी बात यह है कि

अभी इन्होंने पूरी बात कह दी है कि जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये कपड़े का हिसाब-किताब कैसे दे सकेंगे? हर जगह टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो रसीद दिखानी पड़ेगी। इनको कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट रखना पड़ेगा तो इतनी तो इनकी आमदनी भी नहीं है और जिसमें यह बात है कि जो लोग जांच करेंगे, उन्हीं अधिकारियों के यहां सुनवाई होगी तो नेचुरल जस्टिस जो होता है, आपमें से भी कई वकील हैं, आप भी मानते हैं कि नैचुरल जस्टिस भी इनको नहीं मिलेगा। वही कमीशन, वही जांच करने वाले। यह विडम्बना है। आखिर ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं? छोटे-छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों तक को बर्बाद करने का सरकार का डयंत्र है, यह हम मानते हैं। इससे लाभ जो होगा कि जो विदेशी माल के स्टोरेज रखे हैं, उनको यहां लाया जाएगा और यहां का व्यापार और छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह देश का सवाल है, केवल एक व्यापारी वर्ग का सवाल नहीं है। इसका आम जनता पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वैट कानून को वापस लें। यह खतरनाक कानून है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए वर्ना मदनलाल खुराना आप निकल नहीं पाएंगे।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Speaker, Sir, the matter of value-added tax is a concern not only of the Parliament but also of the State Governments. Sir, it is a fact that time and again, the ratio of distribution of revenue share between the States and the Centre has not been a practical one for the last so many years. As a result, the State Governments have to face severe fund crisis one after another and the State Governments cannot create additional revenue chalan. Therefore, the Finance Ministers of the State Governments, irrespective of party lines, at the behest of the Union Finance Minister, under the leadership of the Finance Minister of West Bengal, sat together, discussed and then found a policy which they felt might give some strength to the State Exchequer.

Accordingly, in Stage-I, Finance Ministers of 16 States did agree to implement the concept of Value Added Tax in their own States. The problem here is two-pronged. Firstly, how can the Centre assess the health of the finances of a State and stand by them? Secondly, how can the States create sources of revenue generation to ensure stability of their own finances? We should not bring politics into this. We must objectively understand the whole issue.

The victims at the moment are the small traders, the common traders, who are not equipped to maintain records and papers on the lines of big companies. Therefore, I strongly feel that this entire issue of Value Added Tax should be stayed straight away for one year till the policy of collection is rationalised and infrastructure is put in place. It should be decided as to how the States would manage this collection. A law should be made to free the small traders from harassment.

I will give you an example, Sir, which you will appreciate because you were in the Government. A hawker who sells the loaves of bread produced by Modern Food Industries would not face a problem because the bakery management would keep the records. But, how can a small baker in Rajasthan, a small baker in Bengal, who goes door-to-door in the morning on his bicycle and sells his product maintain this kind of supporting documents and meet the requirements of the Government?

Therefore, my appeal is three-pronged: (1) Let the Standing Committee on Finance go through the matter in depth; (2) Let a Committee of Members of Parliament be appointed, under your authority, to interact with the State Governments and the trading community to know their problems; (3) The entire issue of collection of VAT be stayed throughout the country

till then. This is our appeal number one.

There is another serious problem. The Finance Minister should have been present here. The NDA Government, in the name of shedding tears for the poor, has taken away the facility of excise duty exemption available to the small-scale sector. As a result of that policy of the Government, readymade garment manufacturing industries throughout the country, which are run mostly by uneducated and poor people, are facing a 10 per cent excise duty hike. Yesterday, the people from Mumbai came and met me. I was horrified to know the figures that they gave me. According to the figures, people working in about three lakh garment factories in Maharashtra alone, which are operated by 10 to 20 people each, shall all be unemployed within two days.

Therefore, I request you that these two issues − the issue of readymade garments industry and the VAT − should be stayed immediately and relief should be granted to the small traders. ...(*Interruptions*) If that is not done, the Inspectors will play havoc in the name of rationalisation.

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो विाय सदन में चल रहा है, पहले उसको पूरा होने दें। उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : किसान पानी के बिना मर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किसानों की बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी आप बैठिए। आप अच्छे आदमी हैं। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, रेडिमेड गारमेंट्स पर पहले एक करोड़ रुपए तक एक्साइज ड्यूटी की छूट थी, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। इम इसका विरोध कर रहे हैं औरे कहना चाहते हैं कि वह छूट बहाल होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, तर्क यह दिया गया है कि एक करोड़ वाले बड़े लोग हैं। मैंने उदाहरण दिया कि जैसे बाटा-शू-कंपनी 30 प्रतिशत जूते बनाती होगी लेकिन 70 प्रतिशत जूते हमारे जाटव भाई अपने घरों में बनाते हैं। फरीदाबाद में, आगरा में, कानपुर में लम्बी लाइनें शाम को लगती हैं। ठीक इसी प्रकार से एक आदमी घर में दो-चार मशीने लगाकर कपड़ा बनाता है, कपड़ा सिलता है और जाकर फैक्टरी को दे आता है, उस पर वैट लगाना बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री रामजीलाल सुमन : आपकी सरकार है, आप इसे वापस कराइये। वापस क्यों नहीं कराते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : आप इसमें राजनीति लाना चाहते हैं।â€¦ (व्यवधान)

SHRI RAMJI LAL SUMAN : Sir, he is part of the Governmentâ€¦ (*Interruptions*)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, ये लोग मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए।â€¦ (व्यवधान)मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं और आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :आप वैट को वापस लीजिए।

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please sit down. मेरे सामने लिस्ट है। आप ऐसा सोचेंगे कि शोर मचाकर उनको बोलने नहीं देंगे तो जितना अधिकार आपको है उतना ही उनको भी है। हाउस को डिसीप्लेन से चलने देना चाहिए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, माननीय खुराना जी कह रहे हैं कि वे इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा न हो कि माननीय शांता कुमार जी की तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं प्रारम्भ से ही वैट के खिलाफ रहा हूं। सेंटर का यह कहना कि यह राज्यों का विाय है क्योंकि बंगाल के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बैठी है और इस विाय में राज्य ही तय करेंगे। माननीय दास मुंशी जी ने एक साल की बात कही लेकिन मैं एक बात स्पट कर दूं कि चाहे वैट सारे देश में लागू हो जाए लेकिन अगर वैट दिल्ली में लग गया तो दिल्ली का व्यापार चौपट हो जायेगा। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की बात कीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, उसका कारण है। दिल्ली एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। दिल्ली का 75 प्रतिशत रैवेन्यू सेल-टैक्स से आता है। आस-पास के राज्य चाहते हैं कि दिल्ली का सेल-टैक्स बढ़ाया जाए, जिससे वह टैक्स इन राज्यों के बराबर आ जाए। लेकिन जिस दिन दिल्ली का सेल-टैक्स इनके बराबर आ गया तो दिल्ली का रैवेन्यू आधा रह जाएगा और दिल्ली के कार्य भी आधे रह जाएंगे। चाहे दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, माननीय जगप्रवेश जी की थी या माननीय विजय कुमार जी की थी या खुराना जी की थी, हमने कभी भी आस-पास के राज्यों के बराबर सेल-टैक्स नहीं रखा, कम रखा, क्योंकि दिल्ली में प्रोडक्शन नहीं होता है। दिल्ली में बाहर का माल आता है, 15-20 प्रतिशत यहां खपत होती है और बाकी का माल बाहर जाता है। चाहे बाकी जगह वैट लागू होगा लेकिन दिल्ली के लोग वैट के लिए कभी राजी नहीं होंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : आप सरकार पर दवाब बनाइये और सरकार से वैट को वापस कराइये। â€¦ (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाल के बजट में पावरलूम पर 8 परसैंट उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इससे इस धंधे में लगे करीब 3 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए हैं। पूरी इंडस्ट्री इससे बंद हो गई है। इसे लेकर जगह-जगह मोर्चे निकल रहे हैं और कई जगह लोगों ने आत्मदाह करने की भी वार्निंग दी है। इस कारण सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। इससे संबंधित 60 प्रतिशत उद्योग हमारे महाराट्र में हैं - नागपुर, शोलापुर, इचलकरांजी, मालेगांव, भिवंडी. पढंरपुर, धुलिया में ये उद्योग चलते हैं। इस उद्योग में गरीब लोग जुड़े हैं। यह योजना बड़े लोगों को फायदा पहुंचाएगी। गरीब टाइनी लोग जो इनमें काम करते हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस कारण ये उद्योग बंद हो जाएंगे। इसे लेकर सब जगह आन्दोलन चल रहे हैं। एक तरफ सरकार टैक्सटाइल उद्योग को बचाने के लिए अलग-अलग तरह के आयाम निकाल रही है और नए धोरण बना रही है और जिस उद्योग में तीन करोड़ लोगों के जीवन-मरण का सवाल हो, उसे किल करने का ाडयंत्र चल रहा है। आप इस उद्योग को बचाना चाहते हैं

या मारना चाहते हैं? हम एक तरफ नए रोजगार देने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे उद्योगों को बंद कर रहे हैं। ऐसे उद्योग एक्साइज डयूटी लागू होने से अब काम करने की स्थिति में नहीं हैं। छोटे लोगों को हिसाब-किताब करना नहीं आता है। जो बात वैट के संबंध में व्यापारियों की है, उससे भी खतरनाक स्थिति इन धंधों में काम करने वाले लोगों की है क्योंकि इसमें अनपढ़ किस्म के लोग लगे हैं। जो पावरलूम कारखाने बंद पड़े थे, उन्हें दुरुस्त करके यह उद्योग चलाए जाते हैं। निर्धन और कम लागत वाले ही इन्हें चलाते हैं। इस हाथ से लाओ और उस हाथ से खाओ, इस प्रकार की स्थिति पावरलूम से जुड़े मजदूरों की है। वे उधार लेकर माल लेते हैं तथा उन्हें तैयार करके बेचते हैं। ऐसे लोग अपना हिसाब कैसे रखेंगे? अगर उस पर एक्साइज डयूटी लग गई और उन्हें इस दायरे में लाया गया तो यहां इनसपैक्टर राज आ जाएगा। वे सीधे उनके गले को पकड़ेंगे और उन्हें निचोड़ेंगे। आप इस बारे में कुछ कीजिए। सौभाग्य से मंत्री राणा जी यहां बैठे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह कहें कि पावरलूम को संरक्षण दिया जाएगा। वह इस बारे में कुछ प्रकाश डालें क्योंकि तीन करोड़ जनता से जुडा यह सवाल है। इस वि़ाय में इसमें दूसरी कोई छोटी रियायत नहीं चलेगी। 8 परसैंट जो एक्साइज डयूटी लगायी गई है, उसे एबॉलिश करना ही एकमात्र रास्ता है वरना यह उद्योग समाप्त हो जाएगा और तीन करोड़ जनता का रोजी-रोटी का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वस्त्र उद्योग का वस्त्र हरण करने का यह ड्यंत्र है। अध्यक्ष जी, अगर आप कृ़ण की भांति मदद करने नहीं आए तो पुराना महाभारत फिर होगा। आप महाभारत होने से देश को बचा सकते हैं। आप श्रीकृ़ण की भूमिका निभाइए। वित्त मंत्री और वस्त्र मंत्री को समझाइए।

कि वे जल्दी से जल्दी इस निर्णय को वापस लें और इस संदर्भ में आपको विचार करना है। जैसा श्री पीआर दासमुंशी जी ने कहा कि इसे फाइनैंस की स्टैंडिंग कमेटी को रैफर करें, तब तक आप इस निर्णय को डैफर करिये। इन लोगों को काम शुरु करने की अनुमति दी जाये। यही आपसे आग्रह है और यही आपसे आशा है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसे नियम 193 के तहत बहस में लिया जाये।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में जो एक करोड़ रुपये का टर्नओवर हैâ€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी वि़ाय पर तीन-चार माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी इस वि़ाय पर बोलेंगे। मैंने मंत्री जी से विनती की है, इसलिये वे यहां बैठे हुये हैं। यह वि़ाय महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य सरकार का सहयोग करें। आपका सहयोग मिलेगा तभी मंत्री जी उत्तर दे सकेंगे।

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I associate myself with the issue being raised by the hon. Member.

MR. SPEAKER: Shri Banatwalla, your name will be associated with this.

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, जब कोई महिला बोल रही हो तो कम से कम इन लोगों को बैठ जाना चाहिये।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक ज्वलंत समस्या रेडीमेड गारमेंट्स के बारे मे बोलने की अनुमति दी है, उसके लिये धन्यवाद। रेडीमेड गारमेंट्स के अभी तक एक करोड़ रुपये से ऊपर टर्नओवर पर उत्पादन-कर लगता था लेकिन 2003-04 के बजट में प्रस्तावित कर को समाप्त कर जीरो से उत्पादन कर प्रस्तावित किया है जिससे सम्पूर्ण भारत में लघु कुटीर गारमेंट्स उद्योग समाप्त होकर एक बहुराट्रीय कम्पनी के उद्योग घराने के हाथ में यह सारा काम चला जायेगा। एक करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जायेंगे। सारी फैक्टरियां बंद हैं, लोग धरने और आन्दोलन कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में कोलकाता, मुम्बई, जबलपुर, कटनी से प्रदर्शन लेकर आये हुये हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक करोड़ रुपये का आश्वासन दिया था। उसी के तहत यह कर लागू नहीं होना चाहिये। उचित होगा कि यह कर उसी तरह से समाप्त कर दिया जाये। मेरा आग्रह है कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये और रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्रियां यथावत् रहनी चाहिये और उन्हें पूरा सहयोग दिया जाये, यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर वि़ाय है। रेडीमेट्स गारमेंट्स उद्योग को राहत देने के लिये सरकार की तरफ से कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये क्योंकि लोग धरना दे रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। जब सारा सदन इस बात से सहमत है तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात से मैं खुद को उनसे जोड़ता हूं।

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी खुद को इस वि़ाय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में बोलना था..

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में आधा मिनट दूंगा। में सभी को एक-दो मिनट दूंगा। आप बैठिये।

***SHRI K.K. KALIAPPAN (GOBICHETTIPALAYAM): Sir, I would like to draw the attention of this august House to the sorry state of affairs in the weaving sector and the plight of weavers of this country. The power loom sector is the worst hit due to 10 percent excise duty levied by the Centre ignoring the plea of about 25 lakh of weavers of Tamil Nadu alone. More than a crore of people belonging to weavers' community that is the weavers and their families are greatly affected due to this taxing duty on this small-scale sector. For the past 10 days these weavers have resorted to peaceful agitation methods but the Centre has turned a deaf ear to their woes. The Government of Tamil Nadu led by our leader Dr Puratchi Thalaivi Amma has written to the Centre to attend to the needs of the weavers who are dependent on this occupation which has met with a serious blow due to the severe tax burden brought about by the Union Government recently. I urge upon the Union Government to sympathetically consider the valid plea of the weavers of the power loom sector and take necessary steps to ease the tax burden by way of withdrawing the recently announced 10 percent hike in excise duty. Next only to agriculture weaving industry provide livelihood to thousands of poor people of this country. We must not loose sight of this and we must earnestly make efforts to create a conducive atmosphere for these hapless weavers to continue with their traditional occupation. I urge upon the Union Government to take seriously its textile policy so that no bottle-necks are created in carrying out weaving in the power loom sector and producing garments in the small scale sector.**

***Translation of the speech originally delivered in Tamil.**

...(*Interruptions*)

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, we all want to associate ourselves with the issue being raised.

MR. SPEAKER: Your names will be associated with it.

SHRI ADHI SANKAR (CUDDALORE): Sir, I also associate with it.

MR. SPEAKER: It is good that your Party is also associating with what the Members on the other side of the House have said.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Sir, the entire State of Tamil Nadu is associating with it.

MR. SPEAKER: Yes, the entire State of Tamil Nadu will be associated with it.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराट्र) : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं इस विाय से स्वयं को जोड़ता हूं।

श्री पी.एस.गढ़वी (कच्छ) : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, मैं इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

MR. SPEAKER: Your name will be associated.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले वैट के संबंध में श्री रामजीलाल सुमन और हमारी पार्टी के चीफ व्हिप श्री पी.आर.दासमुंशी जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

इसके बाद मेरी मांग है कि छोटे-छोटे बुनकरों पर 11.2 फीसदी की दर से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। भारत में कुल एक हजार स्पिनर्स हैं। भ्रटाचार और भ्रट अधिकारियों के कारण यह सरकार उनसे एक्साइज ड्यूटी वसूल नहीं कर पा रही है और जिन बुनकरों पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उनकी तादाद दस लाख के करीब है। कहां से ये लोग छोटे-छोटे बुनकरों से एक्साइज ड्यूटी वसूल करेंगे। हालत यह होगी कि एक्साइज ड्यूटी भ्रटाचार का अड्डा बनकर रह जायेगी। इस देश में करोड़ों लोग बुनकर, वीवर्स के काम में लगे हैं, इससे उनकी रोजी-रोटी समाप्त हो जायेगी। इसलिए मेरी मांग है कि बुनकरों पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, उसे तुरंत समाप्त किया जाए, जिससे हमारे देश में छोटे-छोटे बुनकर जो पावरलूम के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, उन्हें अपनी रोजी-रोटी चलाने का अवसर प्राप्त हो सके।

मेरी दूसरी मांग यह है कि गारमैन्ट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक करोड़ रुपये तक की अभी तक रिबेट थी। एक करोड़ रुपये से नीचे का गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स का काम करने वाले लोगों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, उन्हें इसमें छूट प्राप्त थी। लेकिन इस बार 1.4.2003 से भारत सरकार ने उन पर भी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर दी है। दो-दो, तीन-तीन और चार-चार सिलाई मशीन रखने वाले छोटे-छोटे गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स कहां से हिसाब-किताब रखेंगे और कहां से एक्साइज ड्यूटी देंगे। नतीजा यह होगा कि सारे के सारे गारमैन्ट्स मैन्युफैक्चरर्स बंद हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की यही पॉलिसी है और जो अंतर्राट्रीय स्तर की बड़ी-बड़ी फैक्टरीज और कंपनियां हैं, उनके दबाव में इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान पर लागू की जा रही है, जिसमें छोटे-छोटे व्यापारी, गारमैन्ट उत्पादक और बुनकर सब बेरोजगार हो जाएं और सारा माल मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े-बड़े उद्योगपतियों का बिके। मेरी मांग है कि गारमैन्ट मैन्युफैक्चरर्स पर जो एक करोड़ रुपये तक की छूट लागू थी, उसे कायम रखा जाए और एक करोड़ रुपये से ऊपर का व्यवसाय करने वालों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए। इससे नीचे के गारमैन्ट मैन्युफैक्चरर्स पर न लगाई जाए।â€¦ (व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, माननीय विलासराव मुत्तेमवार जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं। महाराट्र में सबसे ज्यादा पावरलूम में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं और उनके ऊपर जो आठ परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, वह बहुत ज्यादा है। आदरणीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। पावरलूम में जितने कर्मचारी होते हैं, उनके घरों में उनकी कमाई से खाने वाले तीन-चार लोग होते हैं। आज उनकी हालत बहुत खराब है। महाराट्र में लगभग तीन करोड़ लोग पावरलूम पर निर्भर करते हैं।

महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप महाराट्र के मुख्य मंत्री थे, तब आपने एम.एस.ई.बी. को बहुत कंसेशन दिया था। तब सारे बुनकरों का काम बंद हो गया था और बुनकरों ने मोर्चा निकाला था। माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने आपको आदेश दिया था कि आप वहां जाकर उनसे मिलिये।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य मंत्री को आदेश कैसे दिया था।

श्री चन्द्रकांत खैरे : विनती की थी और उस कारण से आपने उन्हें बिजली में मदद दी थी। अगर आज आठ परसेन्टâ€¦ (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में एकजुट हैं। जिस मामले में दोनों पक्ष एक हो जाएं तो उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती।â€¦ (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : जब पूरा सदन एक है तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 में इस पर डिस्कशन करा लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अजमेर के अंतर्गत ब्यावर में, किशनगढ़ में 8000 पावरलूम की इकाइयां हैं। एक लाख लोग वहां पर बेकार हो जाएंगे। पावरलूम पर जो इन्होंने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी है, उसके कारण पावरलूम बंद हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वहां पावरलूम की छोटी छोटी इकाइयों को बरबाद होने से बचाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप जवाब दीजिए। मैंने मंत्री जी को इस विाय पर जवाब देने के लिए बुलाया है। रामदास आठवले जी, मैं जानता हूँ कि आपके क्षेत्र में बुनकर हैं और इसीलिए मैं इस विाय पर आपको असोसियेट करने के लिए कहता हूँ।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विाय पर सभी माननीय सदस्यों से अपने को असोसियेट करता हूँ और मांग करता हूँ कि गारमैन्ट्स सैक्टर पर जो एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ाया गया है, उसे वापस लिया जाए* â€¦ (व्यवधान)

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : गारमैन्ट्स पर एक्साइज़ ड्यूटी को वापस लिया जाए। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बजा है। मैं हाउस एडजर्न कर दूंगा तो आप सभी का नुकसान होगा। ये क्या चल रहा है? मैं मंत्री जी से कह रहा हूँ कि उत्तर दो और मैंने मंत्री जी को खास रिक्वैस्ट करके बुलाया है। आप उनको सुनना नहीं चाहते हैं। मैं एक बजे हाउस एडजर्न कर दूंगा। आपका ही नुकसान होगा। Nobody should speak until the reply of the Minister is complete. उनका रिप्लाइ होने दीजिए।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : माननीय अध्यक्ष जी, सदन के बहुत से सदस्यों ने जो पॉइंट यहां पर रखे हैं, जैसे जो स्माल गारमैन्ट मैनुफैक्चरर हैं, जिनको एक करोड़ तक पहले छूट थी, अब उसको एक्साइज़ में कवर कर लिया है। इसके साथ साथ जो पावरलूम सैक्टर है, उसको भी सैनवैट चेन को पूरा करने के लिए एक्साइज़ नैट में ले लिया गया है। â€¦ (व्यवधान)

श्री जी.एम.बनातवाला : उनकोतबाह कर दिया है।

श्री काशीराम राणा : सदन के सदस्यों की जो भावनाएं हैं चाहे वे किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, एक्रास द पार्टी लाइन्स सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें यहां रखी हैं और देश में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसका चित्र उन्होंने यहां पर रखा है। बजट का मैटर होने के कारण मैं सीरियसली इस मामले को वित्त मंत्री जी से टेकअप करूंगा और उसमें से कैसे वह रास्ता निकाल सकते हैं, इस बारे में मैं उनसे बात करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह एक्साइज़ ड्यूटी वापस होनी चाहिए। â€¦ (व्यवधान)

12.59 hrs.

At this stage Kunwar Akhilesh Singh and some other hon. Members came and stood near the Table.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned for lunch to meet again at 2 p.m.

12.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.